तमाम समस्याओं का हल गणपति करेंगे, भाजपा सरकार के वश का नहीं

गणपति के सहारे गोयल

फ़रीदाबाद (म.मो.) गत वर्ष की तरह इस बार भी 13 सितम्बर को उद्योग मंत्री विपुल गोयल, सेक्टर 17 स्थित अपने घर पर गणपति स्थापित कर 5 दिन तक पूजा-पाठ का आयोजन करेंगे। इस दौरान सुबह से रात्रि भोज तक देशी घी के लजीज पकवान खाने को मिलेंगे। मनोरंजन के लिये वॉलीबुड के फ़िल्मी सितारे भी समय-समय पर चमकते रहेंगे। अपने इस आयोजन में सभी आमजनों के अतिरिक्त तमाम पंचों व सरपंचों को भी आमंत्रित किया गया है।

इसी सप्ताह मंत्री महोदय ने शिरडी सांई धाम की यात्रा हेतु यात्रियों की एक बस भी रवाना की थी। इस तरह की उनकी यह शायद चौथी बस है। शिरडी बाबा से प्राप्त होने वाला पुण्य शायद पर्याप्त न लगता हो इसलिये गणपति पूजा का भी आयोजन किया जा रहा है। पूरे ताम-झाम को देखा जाय तो इस आयोजन पर करोड़ों का खर्च बैठना निश्चित है। अभी कुछ माह पूर्व मुरारी बापू की कथा पर भी विपुल गोयल ने करोड़ों खर्च करके भगवान को खुश करने का प्रयास किया था ताकि उनकी समस्यायें हल हो जायें।

उनकी समस्यायें कितनी हल हुई यह तो पता नहीं परन्तु जिस जनता की समस्यायें हल करने का कार्य उनके जिम्मे है, वे ज्यों की त्यों न केवल बनी हुई हैं बल्कि बढ़ती जा रही हैं। गणपति समारोह में सबको आमंत्रित करते हुये उन्होंने कहा कि गणपति सब के दुखहर्ता हैं तथा सुख समृद्धि लाने वाले हैं। यानी मतलब बड़ा स्पष्ट है कि मोदी एवं खट्टर सरकार ने तो जो करना था कर लिया अब तो बस गणपति बप्पा का ही सहारा है।

वैसे राम मन्दिर को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री ने भी कह दिया है कि राम का मंदिर राम ही बनायेंगे और तारीख भी वही तय करेंगे। लगता है इसी तर्ज पर शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सीवर तथा आवारा पशुओं की समस्या भी अब गणपति ही सुलझायेंगे। नहीं सुलझी तो फ़िर से मुरारी बापू को बुलायेंगे और फ़िर भी नहीं सुलझी तो फ़िर गणपति बप्पा तो दोबारा आने को सदैव तैयार रहते ही हैं।

यदि ये सारी समस्यायें गणपति ने या मुरारी बापू ने या शिरडी के सांई बाबा ने ही सुलझानी है तो फ़िर मंत्रियों, संत्रियों व सरकार की आवश्यकता ही क्या है? इस तरह के पूजा-पाठ तो तमाम मंदिरों, मस्जिदों व गुरूद्वारों आदि में चलते ही रहते हैं।

शहर में बढ़ती गुंडागर्दी पुलिस नदारद

फ़रीदाबाद (म.मो.) 10 सितम्बर को कांग्रेस द्वारा भारत बंद के आह्वान को देखते हुये सारी पुलिस को मुस्तैद व अलर्ट पर रखा गया था। पुलिस की इस मुस्तैदी को धता बताते हुये करीब 10-15 लड़कों ने दिन के 11 बजे एनएच 5 एम ब्लॉक चौक पर स्थित विपीन हलवाई की दुकान में घुस कर तोड़-फ़ोड़ करी व विपीन को हॉकी डंडों से जमकर पीटा। उनका यह कांड करीब 10 मिनट तक चला। इसके बाद वे बड़े आराम से टहलते हुये निकल गये।

हमलावरों के दुकान में घुसते ही एक पड़ोसी ने तुरन्त 100 नम्बर पर पुलिस को सूचित किया। लेकिन दो घंटे तक भी पुलिस का कोई अता-पता नहीं था। घटना के करीब दो घंटे के बाद मौके पर पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता धर्मवीर तथा पूर्व मंत्री एसी चौधरी ने पुलिस की इस लापरवाही को देखते हुये तुरन्त एनआईटी के डीसीपी को सूचित किया। डीसीपी ने कहा कि वैसे तो आज वे छुट्टी पर हैं लेकिन फ़िर भी वे पुलिस को मौके पर भेज रही है। लेकिन उसके बावजूद भी जब आधा घन्टा तक पुलिस नहीं आई तो एसी चौधरी ने एसएचओ राठी को फ़ोन किया। इसके करीब 15 मिनट बाद एएसआई रमेश दो सिपाहियों सहित मौके पर पहुंचा। उसने देरी से आने का कारण बताया कि सारी पुलिस भारत बंद में व्यस्त है। उसने उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया और चला गया। जाने से पहले उसने आस-पास के सीसीटीवी फुटेज़ भी देखने का प्रयास किया था।

पुलिस के इस निकम्मेपन से प्रोत्साहित अगले ही दिन फ़िर से शाम 7 बजे के करीब 10-15 लड़के, शायद वही लड़के हों, बाइकों पर सवार होकर उसी एम ब्लॉक के चौक पर हाकी, डंडों,और लोहे की रॉड से लैस हो कर आये और एक घर में घुसकर मार-पीट करके साफ़ निकल गये। तुरंत फ़ोन करने के बावजूद पुलिस एक घंटे बाद मौके पर पहुंची और लकीर पीट कर चली गयी।

दयानंद महिला कॉलेज के सामने स्थित इस ब्लॉक में लगभग सारा दिन आवारा लड़कों के झुंड घुमते देखे जा सकते हैं। उनका जब दिल करता है जिसको मर्जी ठोक-पीट देते हैं। वे इतने बेखौफ़ होकर बड़े आराम से आते-जाते हैं जैसे उन्हें कोई रोकने-टोकने वाला ही न हो। कहावत है कि पुलिस की मर्जी के बगैर उसके इलाके में कोई गुंडा मवाली हरकत नहीं कर सकता।

गुंडा गिरोहों की इस तरह की हरकतें केवल तभी संभव हो सकती है जब थाने का एसएचओ इतना नाकारा हो कि गुंडे उसकी कोई परवाह न करते हो। यदि एसएचओ सही मायने में इलाके का थानेदार हो तो किसी गुंडे मवाली की हिम्मत नहीं कि वह उसके इलाके में ज़रा भी फ़ड़फ़ड़ा सके। इस तरह की गुंडा-गर्दी एसएचओ के लिये निहायत ही शर्मनाक है।

किसानों को समर्थन मूल्य न देने का नया बहाना

फ़रीदाबाद (मा.मो.) किसानों को बेवकूफ़ बनाने के लिये पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने फ़सलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में कुछ वृद्धि करते हुये अपनी पीठ बड़े जोर-जोर से थपथपाई थी। उन्होंने दावा किया था कि उनकी इस कार्रवाई से किसानों की गरीबी दूर हो जायेगी। वैसे तो उनका ये दावा देश की विभिन्न मंडियों में उसी दिन से रोज़ाना झूठा साबित हो रहा है। लेकिन आज हरियाणा सरकार ने इसमें एक और नया पेच फ़ंसा दिया है।

मंडी में बाजरे की नई फ़सल आने लगी है। घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरा खरीदने में असमर्थ सरकार ने एक नया नियम घोषित कर दिया है। इसके अनुसार सरकार उसी किसान का बाजरा खरीदेगी जिसने अपनी फ़सल का पहले से पंजीकरण कराया होगा। यह पंजीकरण हरियाणा सरकार के एक पोर्टल के ऊपर ऑन लाइन होता बताया गया है। इसके अतिरिक्त यह काम कृषि उपनिदेशक के कार्यालय में भी कराया जा सकेगा।

प्रथम दृष्टया देखने से ही यह मालूम पड़ता है कि सरकार की नीयत किसान को भ्रमित करने की है। आज जो किसान मंडी में अपना बाजरा लेकर आ रहा है उसे घोषित समर्थन मूल्य देने की अपेक्षा एक नया ही पहाड़ा पढाया जा रहा है। खट्टर सरकार ने चंडीगढ़ में बैठकर आज यह फ़ैसला तो ले लिया लेकिन इसे किसानों तक पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं की। और यदि यह सूचना किसानों तक समय रहते पहुंचा भी दी जाय तो अधिकांश अनपढ किसानों के लिये इस तरह का पंजीकरण कराना कोई आसान काम नहीं है। लिहाजा वे इस चक्कर बाजी में पड़ने की बजाय अपना बाजरा औने-पौने दामों पर बेचकर निकल लेंगे। जो चतुर-चालाक आढ़ती होंगे वे इस बाजरे को किसी पंजीकृत तथाकथित किसान के नाम पर दिखा कर सरकार से असली समर्थन मूल्य प्राप्त करके मोटा मुनाफ़ा लूटेंगे।

अभी तो ये पेच बाजरे के लिये घोषित किया गया है, लकिन समझा जाता है कि जब धान व गेहूं की फ़सल लेकर किसान मंडियों में आयेगा तो उसे भी इसी तरह दौड़ाया जायेगा। यही भाजपा का असली किसान प्रेम।

मोदी का 4 लाख करोड़ के नए एनपीए का तोहफ़ा देश को

मुकेश असीम की विशेष रिपोर्ट

माल्या के पीछे जो खबर छिप रही है वो ये कि और 4 लाख करोड़ के कर्ज एनपीए होने की ओर हैं और इन्हें चुनाव तक किसी तरह खींचना है क्योंकि एनपीए का बढ़ता संकट पूरी बैंकिंग और आर्थिक व्यवस्था में संकट को अैर गहरा करेगा जिसका बोझ हमेशा की तरह मेहनतकश जनता पर ही डाला जाना है।

इनमें ढाई लाख करोड़ तो सिर्फ विद्युत उत्पादन क्षेत्र का है। पूंजीवाद के अतिउत्पादन के संकट की वजह से उद्योग पहले ही 70-72 प्रतिशत क्षमता पर काम कर रहे हैं इससे बिजली की मांग अनुमान के मुक़ाबले कम है, बिजली बिक नहीं पा रही है (निर्यात के बावजूद भी फालतू है), इसलिए लगभग 40 संयंत्र संकट में हैं। रिजर्व बैंक के 12 फरवरी के सर्कुलर के मुताबिक बैंकों को अब तक इनके खिलाफ दिवालिया होने की कार्रवाई शुरू करनी थी, पर उसके बाद इन कर्जों को एनपीए दिखाना पड़ता जो नहीं किया गया है। पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट से इसको रुकवाने का प्रयास हुआ, मगर असफल। पर अब सुप्रीम कोर्ट ने एक 3 लाइन के आदेश से इसे रोक दिया है।

पर और भी बड़ा मामला है आईएल×एफ़एस समूह का जो भारत का लीमैन ब्रदर्स साबित होने की तरफ बढ़ रहा है और कहीं इसकी चर्चा तक नहीं हो रही है। इसमें सबसे ज्यादा 40 प्रतिशत शेयर एलआईसी व सरकारी बैंको के हैं पर इसे निजी क्षेत्र की तरह चलाया जाता रहा है (दो महीने पहले इसे डुबाने वाला रवि पार्थसारथी सेहत के बहाने रिटायर हो गया है)। यह बैंकों, म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों, आदि दे कर्ज लेकर सड़क, हवाई अड्डा, बांध, विद्युत संयंत्र, आदि जैसे ढांचागत उद्योगों को कर्ज देता है। जहां यह कर्ज देता है वहाँ इसके मूल्यांकन के बाद बैंक और भी कर्ज देते हैं। अब इसके प्रोजेक्ट कमाई नहीं कर पा रहे और नकदी तरलता के अभाव में यह डूबने के कगार पर है। कुछ दिन पहले भुगतान की तारीख पर यह कमर्शियल पेपर की किश्त नहीं चुका पाया, इस महीने और भुगतान की तारीख है। अगले 6 महीने में इसे 3600 करोड़ रु चुकाना है पर इसके पास कुल नकदी की संभावना 200 करोड़ रु ही है। इस पर कुल कर्ज लगभग साढ़े नौ हजार करोड़ रु है। पर इससे भी बड़ी बात ये कि इसके प्रोजेक्ट्स को सीधे बैंक कर्ज और भी बड़ी मात्रा में, संभवत: डेढ़ लाख करोड़ रु के फेर में हैं जिनको भी अंतत: एनपीए वर्गीकृत करना पड़ेगा।

देखना है कि क्या मोदी सरकार इसे भी आईडीबीआई की तरह इसके सबसे बड़े शेयरधारक एलआईसी के ही गले बांधकर संकट को टालेगी, क्योंकि इस राह आखिर में संकट एलआईसी तक भी पहुंचेगा ही जिसमें मध्यमवर्गीय लोगों ने संकट के जोखिम से निपटने के लिए भारी पैसा लगाया हुआ है, और जो वास्तव में एसबीआई से भी बड़ा वित्तीय संस्थान है।

कुछ ऐसा बजेगा 'आयुष्मान भारत' का झुनझुना

फ़रीदाबाद (म.मो.) बिना डॉक्टरों व अस्पतालों के देश भर के 50 करोड़ लोगों को चिकित्सा सेवा देने वाला प्रधानमंत्री मोदी का 'आयुष्मान भारत ' पूरी तरह से फ़्लॉप हो चुका है। अब तक न तो किसी बीमा कम्पनी ने बीमा करने की हामी भरी है और न ही किसी अस्पताल ने। लेकिन मोदी सरकार के इस अति महत्वाकांक्षी दावे को आगामी चुनावों तक किसी तरह ज़िंदा रखने के लिये एक सरकारी बीमा कम्पनी ओरियंटल को जबरन तैयार किया गया है।

इसी तरह जब किसी भी निजी अस्पताल ने, इस योजना में घोषित दरों एवं शर्तों पर काम करने से साफ़ इन्कार कर दिया तो सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों के माध्यम से चुनावों तक इस झुनझुने को बजाते रहने का प्रयास किया जा रहा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार हरियाणा सरकार ने गत सप्ताह करनाल के अपने मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक गर्भवती महिला की सीजेरियन ऑपरेशन द्वारा डिलिवरी करा कर अपने ही अस्पताल को घोषित दर के हिसाब से 9000 रुपये की पेमेंट करके मोदी को बता दिया कि उन्होंने उनके आदेशानुसार 'आयुष्मान' का झुनझुना बजाना शुरू कर दिया है। विदित है कि तमाम सरकारी अस्पतालों में इलाज लगभग मुफ़्त होता है।

इसी तर्ज पर स्थानीय बीके अस्पताल सहित राज्य के तमाम सरकारी अस्पतालों में इस तरह की ड्रामेबाज़ी चलेगी। इस ड्रामेबाज़ी को ठीक से चलाये रखने के लिये सरकार ने फ़ैसला किया है कि 'आयुष्मान' बिल की पेमेंट से जो पैसा (सरकारी) अस्पतालों में आयेगा उसका एक बड़ा हिस्सा सम्बन्धित डॉक्टरों व स्टाफ़ में बांट दिया जायेगा। इसका परिणाम यह होगा कि तमाम सरकारी अस्पतालों में अब दो लाइनें लगा करेंगी; एक वे जिन्होंने किसी जुगाड़बाज़ी से 'आयुष्मान' कार्ड बनवा लिया हो और दूसरी लाइन में वे गरीब एवं बेसहारा लोग होंगे जिनके पास इस तरह का कोई जुगाड़ नहीं है।

सर्वविदित है कि बीके समेत राज्य भर के तमाम सरकारी अस्पतालों में जरूरत के आधे भी न तो डॉक्टर हैं न अन्य स्टाफ़ व उपकरण आदि। इसके चलते अस्पतालों में मरीज़ों की लम्बी-लम्बी लाइनें लगी रहती है। जाहिर है इन अस्पतालों में केवल वही मरीज़ आते हैं जिनके पास महंगे निजी अस्पतालों में जाने की सामर्थ्य नहीं होती। अब इस 'आयुष्मान' के चक्कर में इन ग़रीबों को भी दो भागों में बांट कर सरकार भारी रोष पैदा करने जा रही है। दरअसल जरूरत तो थी नये अस्पतालों व पर्याप्त मात्रा में डॉक्टरों व स्टाफ़ की; बीते साढे चार साल में इस दिशा में मोदी व खट्टर सरकार ने किया कुछ भी नहीं। अब चुनाव सिर पर आये तो यह ड्रामेबाज़ी शुरू कर दी।